SK/2B/2.00

The House reassembled after lunch at five minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS (CONTD.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yesterday, Shri D. Raja completed his speech.

(Contd. by YSR/2C)

-SK/YSR-VNK/2.05/2C

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Mr. La. Ganesan did not start. One round is complete. That is the position.

SHRI SITARAM YECHURY: We did not speak. How did you complete one round?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One round complete means those who were here to speak.

SHRI SITARAM YECHURY: If we were called and we were not here that I can understand. But that also did not happen.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You were not here.

SHRI SITARAM YECHURY: I was not here. But you did not call.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The point is, if I start with Mr. Ganesan that will be considered as second round. Then after him, Mr. Rajeev Shukla will speak. Then Mr. Sanjay Seth will speak. Then will come the turn of the AIADMK. Then Shri Sharad Yadav will speak. Then Shri Sitaram Yechury will speak. Since you and Sharad Yadavji did not speak on that day, your turn will come in the second round. Shri La. Ganesan, your party has allotted you only ten minutes. You have to speak within ten minutes.

श्री ला. गणेशन (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं तमिलनाडु से आया हूँ। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तमिलनाडु में हिन्दी सिखाने की व्यवस्था नहीं है। हिन्दी सीखने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है, इसलिए मैं हिन्दी नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कारण यह है कि मैं मध्य प्रदेश से चुन कर आया हूँ। ...(व्यवधान)...

SHRI JAIRAM RAMESH: *Speak in Tamil. Speak in Tamil.

SHRI LA. GANESAN: *When I speak in Hindi, there are only very few people to listen. If I speak in Tamil, who will listen?

SHRI JAIRAM RAMESH: *Speak in Tamil. Speak in Tamil.

SHRI LA. GANESAN : Thank you for supporting me to speak in Tamil.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why not in Telugu?

*** English translation of the Tamil portion.**

श्री ला. गणेशन : ये चाहते हैं कि मैं तमिल में बोलूं। मेरे द्वारा हिन्दी में चार सेंटेंस बोलने के बाद उनको मेरी हिन्दी कष्टप्रद लगने लगती है, इसलिए वे मुझे तमिल में बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत से हिन्दी में ही बोलने की कोशिश करूंगा।

अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं मध्य प्रदेश की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि, मान्यवर मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे मौका देने के लिए मैं प्रधान मंत्री जी और अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं हिम्मत से हिन्दी में बोलना शुरू करता हूँ, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि मैं जो बोलता हूँ, वह हिन्दी ही है, ऐसा आपको मानना चाहिए। पिछले सेशन में यहां पर पहली बार आने के बाद मैंने देखा कि यहां पर स्लोगन और काउंटर स्लोगन, एड्जर्नमेंट और एड्जर्नमेंट हुआ। यहां पर इस तरह देख कर मेरे मन में बहुत दुख हुआ। मेरे मन में कल्पना थी कि यहां पर मुझे अच्छी तरह बोलने वाले वरिष्ठ नेताओं के मुख से अच्छे-अच्छे भाषण सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन जो देखने को मिला, वह इससे अलग था। तमिलनाडु में एक कहावत है, 'Balakumara, you desired only for this. Didn't you?' मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन इस बार सदन अच्छी तरह से चल रहा है और वक्ताओं को बोलने का मौका मिलता है तथा बाकी लोगों के भाषण को सुनने का भी मौका मिलता है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ।

(2डी/एनकेआर-वीकेके पर जारी)

NKR-VKK/2D/2.10

श्री ला. गणेशन (क्रमागत): मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अलग से देखना उचित नहीं है बल्कि समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। देश में, 2014 में, आम चुनाव होने के बाद, मान्यवर नरेन्द्र मोदी के प्रधान मंत्री पद ग्रहण करने के बाद, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सैशन में जब मान्यवर राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण दिया, मुझे याद है, हमने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व जो अपना घोषणापत्र, election manifesto, रिलीज़ किया था, हमने चुनाव के समय जो वायदे किए थे, जिन्हें घोषणापत्र में लिखा था, उसके सभी अंशों को, all those points which were mentioned in the manifesto were incorporated in the Presidential Address. इसका अर्थ यह हुआ कि बी.जे.पी., यानी मेरी पार्टी ने चुनाव के समय घोषणापत्र में जिन वायदों को शामिल किया, वे केवल वोट मांगने के लिए नहीं किए, बल्कि जीतने के बाद उन सभी वायदों पर सीरियसली implementation करने, उन पर अमल करने की हमने कोशिश की और उन सबको हमने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में शामिल किया। It is a progress report and accountability. इन दो सालों में हमने क्या किया, उसकी accountability - one-by-one - सभी स्कीम्स को शामिल करके इस साल का अभिभाषण कराया। उसके बाद, अपनी बजट स्पीच में, हम आगे क्या करने वाले हैं, अपने वित्त मंत्री जी ने उन स्कीमों को शामिल करके इस साल का बजट पेश किया है, जिस पर हम अलग से चर्चा करने वाले हैं। फिर भी, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आए एक-दो मुद्दों पर मैं यहां बोलना चाहता हूं।

जब माननीय लालबहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उन दिनों टी.वी. नहीं होता था लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में जब हमने शास्त्री जी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि देश कष्ट में है, हमें खाने को चावल नहीं मिलता और उन्होंने देशवासियों से अपील की - I appeal to the people - कि हर सोमवार रात्रि उपवास करना चाहिए, मैंने तुरंत उस अपील का पालन किया। उनकी अपील का पालन करने में आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। उस समय मैं एक सरकारी कर्मचारी था। मेरे अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों ने भी उनकी अपील का पालन किया, क्योंकि शास्त्री जी में आम जनता का बहुत विश्वास था। आपको अभी भी याद होगा, जहां लालबहादुर शास्त्री जी की अपील का जनता ने पालन किया, उसके बाद अगली बार, जब मान्यवर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एल.पी.जी गैस consumers से अपील की कि जो लोग समर्थ हैं, उन्हें गैस सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, तुरंत एक करोड़ बीस लाख लोगों ने अपना सब्सिडी वापस कर दी। इसका अर्थ क्या है? यह आश्चर्य का विषय है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आम जनता में कितना विश्वास है, यह उसे प्रदर्शित करता है।

दूसरा विषय है कि आज सब लोग बोलते हैं कि देश की पॉपुलेशन में पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम हो रही है। यह जो परसेंटेज़ में फर्क है, उसके लिए क्या करना है, बेटी के लिए क्या करना है, उसकी चर्चा आज भी हुई है।

(डीएस/2E पर जारी)

-VKK/BHS-DS/2E/2.15

SHRI LA. GANESAN (CONTD.): There is one another demography, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। मैं सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग विरोध करेंगे। यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। जैसे प्रधान मंत्री जी ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" की घोषणा की है, उसी प्रकार "बेटी बढ़ाओ" के लिए भी एक घोषणा की जानी चाहिए। हर एक घर में एक बेटा-दो बेटी, ऐसी अगर एक घोषणा की जाती है, तो उससे बेटियों की संख्या अधिक होगी। मेरा सुझाव है, "एक बेटा-दो बेटी, रक्षा करेंगे देश की माटी" यह स्लोगन भी हम दे सकते हैं।

इस चर्चा की शुरुआत में मैंने प्रतिपक्ष के नेता का भाषण सुना। यहाँ आने के बाद मुझे उनका भाषण बार-बार सुनने का मौका मिला है। उनकी आवाज इतनी सुन्दर है कि जब मैं उनको सुनता हूँ, तो वह मुझे बहुत पसंद आती है। गुलाम नबी आज़ाद जी आज सभा में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज अच्छी है, सुन्दर है, लेकिन विषय के बारे में कुछ विरोध करने की बात भी है। उन्होंने कश्मीर के बारे में बताया। कश्मीर के बारे में बोलते समय उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली आम जनता को कितना कष्ट है, उनके लिए सुविधा नहीं है आदि। मेरे मन में बहुत कष्ट हुआ। मुझे जो कष्ट हुआ, उसका कारण यह है कि कांग्रेस सत्ता में 60 साल तक रही और 60 साल तक सत्ता में होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता अगर यह बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली आम जनता को इतना कष्ट है, तो इसका कारण क्या है? Who is responsible for that?

उन्होंने दूसरा विषय यह बताया कि वहाँ हमारे बहुत-से जवान हैं। More Forces are there. He has mentioned about that also. मैं पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में इतनी अधिक फोर्सेज़ क्यों हैं? ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : आपका 10 मिनट का समय समाप्त हो गया।

श्री नारायण लाल पंचारिया : अगले वक्ता का टाइम कम कर दीजिएगा।

श्री उपसभापति : बाकी और लोगों का समय कम कर दूँ?

श्री नारायण लाल पंचारिया : जी हाँ, सर।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप बोलिए।

श्री ला. गणेशन : एक हॉस्पिटल में सैंकड़ों पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जब एक ही पेशेंट के पास चार-पाँच डॉक्टर्स बार-बार जाते रहें, तो उसका कारण यह होता है कि वह पेशेंट सीरियस होता है। That is the reason. पूरे देश के मुकाबले कश्मीर में अधिक Armed Forces हैं, तो इसका कारण यह है कि कश्मीर की स्थिति खतरनाक है, वहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कर्फ्यू के बारे में अपनी बात कही, लेकिन वह कर्फ्यू क्यों लगाया गया? उसका कारण क्या है, उसके पीछे कौन है, इसके बारे में आप एक वाक्य भी नहीं बोले। मैं तमिलनाडु से आया हूँ। आप कश्मीर से हैं और मैं कन्याकुमारी से हूँ। Though I am from Chennai, Tamil Nadu, I am very much concerned about the people of Kashmir. मैं कश्मीर के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि कश्मीर के बारे में सोचने और उसके बारे में बोलने का मेरा अधिकार है। उसका नाम कश्मीर इसलिए पड़ा, क्योंकि it was a Kashmir *Maharishi*, जिनके कारण

उसका नाम कश्यपनीरम् पड़ा, जो आजकल कश्मीर हो गया है। ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा है। मैं कश्यप गोत्र में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे यह अधिकार है। भारत एक देश है, ऐसा मैं सोचता हूँ, इसलिए मुझे यह अधिकार है। लेकिन, आपको भी सोचना चाहिए कि आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है? The people those who are inspired by Pakistan, वैसे उग्रवादियों के हाथों तमिलनाडु में 130 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता और अलग-अलग हिन्दू संगठनों में काम करने वाले लोग शामिल थे। यह अभी भी चल रहा है, लेकिन उनके बारे में आप नहीं बोलते हैं। कश्मीर में इतनी मिलिट्री फोर्सेज़ क्यों हैं, आप केवल इस बारे में बोलते हैं। आप पूरे देश के बारे में बोलिए। आपकी राष्ट्रीय पार्टी है और आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, इसलिए पूरे राष्ट्र के बारे में आपको भी चिन्तन करना है, सोचना है, यह मेरी प्रार्थना है। इसके अलावा, एक और दूसरा विषय भी है।

(2एफ/एमसीएम पर जारी)

MCM-DC/2F/2.20

श्री ला0 गणेशन (क्रमागत) : दूसरा विषय है, पांच सौ रुपये का एक नोट मिला है। एक साइड से यह तो आधा साफ है, सिम्पली व्हाइट है और केवल आधा प्रिंटेड है। Sir, exception makes the rule. अगर कोई पांच सौ का नोट खराब है तो यह मसला पार्लियामेंट में देखने के लिए, बोलने के लिए विषय नहीं है। इसके लिए रोज अखबार में छापते हैं। It is an exception because man has bitten the dog and, that is why, they have printed it in the newspaper. I never expected that such a small

thing will be raised in this august House by a senior leader. उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया है। पूरे विदेश के अखबारों में demonetization के बारे में क्या-क्या छपा है, क्या-क्या article है। He has studied all the newspapers that publish in foreign countries but they have not studied the mood of the आम जनता of India. आम जनता अलग सोचती है तथा वह demonetization को सपोर्ट करते हैं। Demonetization घोषित करने के बाद हुए सभी चुनावों में, even we have won in many places where we had not at all won so far. The people are with us. So please study the mood of the people before studying the articles published in other countries. This is my only request. .....(समय की घंटी)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri La. Ganesan, now please conclude.

SHRI LA. GANESAN: Sir, I will tell you here that I never expected that I would be called yesterday. That is why मैं विस्तार से बोलने के लिए तैयारी करके आया हूं, लेकिन आप बोलते हैं, and I am a disciplined soldier, so मैं अब समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : धन्यवाद उपसभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो माननीय विधि और न्याय मंत्री लाए हैं, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, अमूमन मैं पिछले कई सालों से धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलता रहा हूं,

पिछले दो साल मैंने जान-बूझ कर सरकार की आलोचना नहीं की थी, क्योंकि मैं उनको कहता था कि जब कोई चुनकर आए तो उनकी तुरन्त आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए कि वह अपने कार्यक्रमों को लागू करे, अपनी नीतियों को लागू करे, अपने फैसलों को लागू करे। इसलिए अपनी कंस्ट्रक्टिव स्पीच उस समय दी थी कि यह सरकार कुछ करेगी। लेकिन पौने तीन साल बाद राष्ट्रपति जी का यह तीसरा अभिभाषण है और मैंने पाया कि इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिसकी सराहना की जाए। उसको लेकर, उसको पढ़कर काफी निराशा हुई, क्योंकि यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जो सरकार देती है और राष्ट्रपति जी अपनी सरकार के उस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो सरकार है उसको काम करने के अब डेढ़ साल बचे हैं, क्योंकि आखिरी 6 महीने तो चुनावों के कारण लग जाते हैं। अभी तक जो उनका रिकॉर्ड है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो देश को राहत प्रदान कर सके, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे सामाजिक मोर्चे पर हो, चाहे किसी मोर्चे पर हो। तो इसलिए यह अभिभाषण सुनकर हमें बहुत निराशा हुई है। आज मैं यह समझता हूं कि सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, खास तौर से पार्टी के लोग। जिस तरह से ये लोग महिमामंडन में लगे हुए हैं उसके बजाए जो सही फीड बैक, सही बात है, अपने नेता को बताएं, तो शायद स्थिति में बदलाव आए, लेकिन कोई बतलाता नहीं। सेंट्रल हॉल में बैठकर आलोचना करते हैं ये लोग, लेकिन वहां जो है, उनको सही पिक्चर, तस्वीर नहीं देते कि क्या स्थिति नीचे है, क्या जमीन पर स्थिति है। वे कहते हैं सब सही चल रहा है, हर चीज गुलाबी है, रोज़ी पिक्चर उनके सामने रखी

जाती है और यहां पर बोलते भी हैं। ठीक है, वह नौकरी का खतरा होता है, जो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए तो बताना चाहिए कि असलियत क्या है। चाय-कॉफी पर सेंट्रल हॉल में चर्चा होती है, वहां अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन बाहर जो स्थिति है, वह सदन में आकर, उनके पास मिलकर नहीं कहते। मैं तो उनको 20 साल से जानता हूं, वे सुनेंगे। ऐसा नहीं है, प्रधान मंत्री बहुत व्यस्त होता है, उसके ऊपर रात दिन इतना काम होता है, मैं तो प्रधान मंत्री के डॉयरेक्टली अंडर में काम कर चुका हूं, इतना काम होता है कि उनको फुर्सत नहीं होती। आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनको बताएं, उनको समझाएं। वे सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई बताता नहीं। आज मैं पूछता हूं कि अगर सब ठीक है तो किसान क्यों दुखी है, मजदूर क्यों दुखी है, दुकानदार क्यों दुखी है, व्यापारी क्यों दुखी है, आम आदमी क्यों दुखी है, जो टूरिस्ट आ रहा है, वह परेशान है। हर तरफ तो लोग आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक है। यह वैसे ही है जब सरकार को 8 साल हो जाते हैं, तब इस तरह का अहंकार आता है, तब इस तरह का लगता नहीं है कि सब ठीक है।

(2G/SC पर जारी)

SC-KR/2.25/2G

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत) : अब यह ढाई-पौने तीन साल में हो गया है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। यही मुझे उधर से सबके भाषण में लग रहा है,

चाहे प्रस्तावक का भाषण हो, जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है, चाहे समर्थक का हो या बाकी लोगों का हो, जिन लोगों ने भाषण दिया है।

आज आप किसान को देखिए। उसे न बीज मिल रहा है, न खाद मिल रही है। उसे अपना सामान फेंकना पड़ रहा है। आप सब भी इस बात को जानते होंगे कि आलू और टमाटर का दाम कितना सस्ता हो गया, पांच रुपए, दस रुपए किलो हो गया। उसने अपना सारा सामान फेंक दिया क्योंकि उसका सारा माल सड़ गया था क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखने की कीमत इतनी अधिक थी कि वह उसे बरदाश्त नहीं कर सकता था, बाज़ार में उसे अपने सामान की उतनी कीमत नहीं मिल रही थी। इस प्रकार किसानों का यह हाल हो रहा है। उन्हें अपना समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जो आपने वायदा किया था। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं आ रही है, जो लागत लगती है। इस प्रकार किसान बहुत बुरी हालत में है। माननीय आज़ाद साहब ने आंकड़ा दिया कि 36 प्रतिशत किसानों ने आत्महत्या की। हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको देखने और समझने की जरूरत है। मेरा आपको सुझाव है कि आप इस तरफ ध्यान दें। किसान बेहद दुखी और परेशान हैं। दूसरी तरफ दुकानदार हैं। छोटे-छोटे करोड़ों दुकानदार त्रस्त हैं, सब परेशान हैं। किसी का माल नहीं बिक रहा है, फैक्टरियां बंद हो रही हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं। आप देखिए कि कितनी ट्रेनें भरकर जा रही हैं। कोई छठ पूजा नहीं है, फिर भी बिहार, ओडिशा और बंगाल की ट्रेनें भरी हुई हैं क्योंकि सब मज़दूर वापस जा रहे हैं, फैक्टरियां बंद हो गयी हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अर्थव्यवस्था में जीडीपी नीचे जा रहा है। यह चीज़ भी देखने लायक है कि

लोगों की कितनी बुरी हालत हो रही है। उसको अगर आप सिर्फ यह समझें कि चूंकि हम आलोचना कर रहे हैं, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं देना है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं, कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं।

आप जीतने की बात करते हैं। मैं आपको महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूं। वहां पर 2,100 नगरपालिकाएं हैं। आप कहते हैं कि हम जीत गए। वहां 600 सीटें बीजेपी को मिलीं, 500 के करीब एनसीपी को मिलीं, 480 कांग्रेस को और 490 शिवसेना को मिलीं। कांग्रेस भी नोटबंदी की आलोचना कर रही थी, शिवसेना भी नोटबंदी की आलोचना कर रही थी और एनसीपी भी नोटबंदी की आलोचना कर रही थी। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 1,500 से 1,600 जगह आप हारे, सिर्फ 600 जगह ही तो जीते। अगर आप नोटबंदी को mandate मान रहे हैं, तो फिर इसे जीत कैसे कहेंगे? कॉर्पोरेशन और छोटे-छोटे निकायों में नोटबंदी के बाद 1,600 जगह आप हारे और 600 जगह जीते। अगर नोटबंदी पर mandate है तो एक तरह से यह mandate आपके खिलाफ था। इसलिए आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि नगरपालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव में नोटबंदी की वजह से आपको वोट मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बातें आपको सही रास्ते पर ले जाएंगी, इसलिए आपको यह सब देखना पड़ेगा। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिज़नेस हो, आप लोगों को रोज़गार कैसे देंगे? आपने कहा कि दस करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज manufacturing sector, छोटी-छोटी इकाइयों और उद्योगों का बुरा हाल है, वे सब बंद हो रहे हैं। सबके पीछे इंस्पेक्टर लगा हुआ है। जहां देखो, आपने एक ही काम किया है कि डंडा लेकर हरेक के पीछे इंस्पेक्टर

लगा हुआ है। आज करोड़ों नोटिस issue होंगे - आज इसको नोटिस, कल उसको नोटिस - हर डिपार्टमेंट लगा हुआ है तो रोज़गार कौन देगा? अगर वे सब भाग जाएंगे तो रोज़गार कौन देगा? आप दुबई के अपने Consulate General की लिस्ट मंगा लीजिए कि आज कितने लोग दुबई में जा-जाकर बस रहे हैं और Emirates Hills में घर ले रहे हैं क्योंकि भगदड़ मची हुई है। इसलिए यह चीज़ देखने, सोचने और समझने की है। आप यह मत समझिए कि हम आप पर कोई आरोप लगा रहे हैं या आपकी आलोचना कर रहे हैं। इस चीज़ को देखने की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। Cashless Economy अच्छी है, आप शुरू कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे-धीरे कीजिए, डंडा मारकर एक दम नहीं करा दें, यह बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था का आपको पता ही है कि जीडीपी का क्या हाल है। आज तो यह रिपोर्ट भी आयी कि डॉलर 70 रुपए का हो जाएगा। जब चुनाव हुए थे तो आपने वायदा किया था कि हम डॉलर को पचास रुपए पर ले आएंगे, वह भी आपके एक वायदे में शामिल था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसा आपने कहा कि नोटबंदी करने का आपका मुख्य मकसद काले धन पर रोक लगाना था। क्या एक रुपए का भी काला धन आया है, इस पर सरकार जवाब दे? मुझे नहीं लगता कि एक रुपए का भी काला धन आया, बल्कि जिनके पास काला धन था, उन्होंने भी सफेद कर लिया, बैंकों में चला गया। तो या तो काले धन की परिभाषा गलत थी, जिस पर आप काम कर रहे थे या आपने पूरा होमवर्क नहीं किया था। यह चीज़ समझने की है, जिसका आपको जवाब देना चाहिए।

दूसरा, आपने जाली नोट और आतंकवाद के बारे में कहा। आतंकवादियों के पास लबालब लाल नोट निकल रहे हैं। इसका मतलब उन्हें भी सब मिल गया। इस प्रकार न इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो पायी और न आप काले धन की लड़ाई लड़ पाए, केवल लोग त्रस्त और परेशान हुए और इसका economy पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, इसलिए यह चीज़ भी समझने की जरूरत है।

तीसरा, जो संवैधानिक ढांचा है, जो संस्थाएं हैं, उनके संबंध में यह आपका प्रयोग है। मैं नहीं कहता कि आप प्रयोग मत कीजिए - हर सरकार करती है, यह आपका प्रयोग है, लेकिन सोचना-समझना चाहिए, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपने योजना आयोग खत्म कर दिया और नीति आयोग बना दिया। वहां नीति कम, राजनीति ज्यादा है। पहले मैं योजना मंत्री था, योजना आयोग में बैठता था। कुछ न कुछ प्लानिंग, कुछ न कुछ अंकुश, कुछ न कुछ समीक्षा होती थी। अब तो पता ही नहीं चलता कि नीति आयोग कर क्या रहा है? नीति आयोग में क्या हो रहा है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पहले हर मुख्य मंत्री को वहां पर अपनी बात रखनी पड़ती थी - ठीक है, कुछ मुख्य मंत्रियों को उसका बुरा लगा होगा कि क्यों जाना पड़ता है?

(2एच-जीएस पर जारी)

KS-GS/2H/2.30

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत): लेकिन एक परम्परा थी। कोई मुख्य मंत्री जब केन्द्र में मंत्री हो जाते हैं, प्रधान मंत्री हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि मुख्य मंत्रियों की जवाबदेही होनी चाहिए, राज्यों की जवाबदेही होनी चाहिए। जब तक वे राज्यों में रहते

हैं, तब तक उन्हें लगता है कि कोई अन्याय हो रहा है। सब मिल-जुल कर सभी स्कीमों पर काम करते थे। योजना आयोग में चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसने तमाम योजनाओं को, स्कीमों को खत्म करने की बात कही थी, उसका कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है? बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जिनका पैसा नीचे तक पहुंचता ही नहीं है, सिर्फ कागजों पर रह जाता है या ब्यूरोक्रेसी में गड़प हो जाता है। उन सारी योजनाओं का क्या हुआ? उन सारी योजनाओं पर जो काम चल रहा था, उस काम का कहीं पता नहीं चल रहा है कि वह कहां पर है? इसी तरह से FIPB आपने खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका alternative system क्या रहेगा, यह लोगों को नहीं पता कि कैसे क्लियरेंस लोगों को FIPB पर मिलेगी?

आपने रेल बजट खत्म कर दिया। प्रभु जी की ऐसी लीला हुई बेचारों की कि उनका जलवा ही खत्म हो गया। उनका कुछ पता नहीं, हाउस में भी आने में बेचारे शरमा रहे हैं। क्या जलवा होता था, दो राज्य मंत्री साथ होते थे, उनके फोटो खिंचते थे। पूरा एक दिन शानदार होता था, सब लोग चर्चा करते थे, बहस होती थी, अब पांच मिनट में रेल बजट समाप्त हो गया। पूरी परम्परा खत्म हो गई, उसमें सिर्फ क्या allocation और provision है, सिर्फ इतना पता चला, आगे क्या डिटेल है किसी को कुछ पता नहीं, तो रेल बजट भी खत्म कर दिया।

आर.बी.आई. की स्वायत्तता को लेकर पहले से ही आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आपको कहीं न कहीं यह सोचना चाहिए कि इन संस्थाओं के बारे में क्या हुआ। इन

संस्थाओं का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, वह उचित है या इसका कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी आपको सोचने की जरूरत है।

उपसभापति जी, कुछ चीजों का इसमें जिक्र ही नहीं है, जैसे गंगा का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना हो-हल्ला हुआ, ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या हो जाएगा? चूंकि गंगा जी के स्वच्छीकरण के लिए कोई इस तरह का कारगर चीज़ हुई नहीं, इसलिए "नमामि गंगे" का कोई जिक्र ही नहीं है। वह सब्जेक्ट ही गोल कर दिया।

विदेश नीति की बात आती है, विदेश नीति में कहीं न कहीं.. सुषमा जी बहुत बीमार हैं, हम सब उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ हों। उनकी तरफ से जितनी कोशिश होती है, वे करती हैं। वे ट्विटर के माध्यम से सहायता करने की कोशिश कर रही हैं। आज आप देखिए कि सब पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़ गए हैं। अब अमेरिकी सरकार का जो रुख है, कोई भी बात उनसे की हो, वहां पर लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, जो काम आउटसोर्सिंग का मिलता था, हमारी आई.टी. कम्पनियों को मिलता था, वह भी खतरे में आ गया है, तो कहीं न कहीं विदेश नीति पर भी प्रधान मंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा कि सब कुछ सही नहीं है। हमारे अपने सभी पड़ोसियों से रिश्ते खराब हैं। पाकिस्तान से तो रिश्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं। जबकि उन्होंने पहल की थी, अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज़ शरीफ को बुलाकर, उनकी पोती की शादी में जाकर, उन्होंने पूरा गले लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका परिणाम देश के हित में आया हो, ऐसा नहीं है। जब हम सरकार में थे, तो हमारी बड़ी आलोचना होती थी। अगर हम धोखे से भी लाहौर की तरफ मुंह कर लेते थे या

इस्लामाबाद की तरफ देख लेते थे, तो हमारी इतनी आलोचना होती थी कि पता नहीं हमने कौन सा अपराध कर दिया। आपने पूरा गले लगाया, सब किया, इसकी हमने तो सराहना की, अच्छा है, रिश्ते मजबूत करने चाहिए, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आया है। सर्जिकल स्ट्राइक - यह पब्लिसिटी लेने के लिए नहीं है। हर चीज़ को इवेंट बनाओ, मार्केटिंग करो, हंगामा करो और उसके बाद असलियत में वह विवादास्पद बन जाए। देखिए, ओवर मार्केटिंग हर चीज़ की, नुकसान करती है, ओवर पब्लिसिटी हर चीज़ में नुकसान करती है। हमारी सरकार में भी तीन बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और यह आर्मी का काम है, वह ऐसा करे। लेकिन ऐसा लगा कि यह पहली बार हुआ है। हमें तो यह घबराहट हुई कि कहीं इस्लामाबाद पर कब्जा तो नहीं हो गया है, जिस तरह से चारों तरफ से हंगामा हो रहा था, पता ही नहीं लग रहा था। जब इंदिरा जी ने 1971 का युद्ध लड़ा था, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। इस तरह से लग रहा था कि रक्षा मंत्री कोई गदा लिए हुए आगरा में खड़े हैं, कोई बाण लिए हुए खड़ा हुआ है, कोई कुछ लिए खड़ा है, पता नहीं क्या-क्या कर दिया । आखिर में जनरल को खड़े होकर कहना पड़ा कि भाई साहब, यह तो पहले भी हो चुका है, तब यह बात खुली। फिर विदेश सचिव को बोलना पड़ा कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हो चुकी है, यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे काम 26 मई, 1914 के बाद ही हुए हैं, उसके पहले भी देश में बहुत काम हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे जो सरकारें रही हों। यह जो attitude है, इसके कारण प्रॉब्लम आती है। इतनी ज्यादा

पब्लिसिटी कर देते हैं कि उससे दिक्कत आती है, मुझे दुष्यंत कुमार का शेर याद आ रहा है -

" अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार,
घर की दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार ।"

ये जो आपने इश्तिहार चिपका कर दरारें छिपा रखी हैं। यह आपके हित में नहीं है, क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा, हवा अंदर आ जाएगी, ठंड अंदर आ जाएगी। इससे आपको ही नुकसान होगा। इसलिए इश्तिहार हटाओ और दीवार की दरारों को भरने का काम करो। तभी जाकर होगा, इसमें आप सोचो कि हम आलोचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हां, आपने स्वच्छता अभियान शुरू किया, यह अच्छी बात है। इसको गांधी जी ने शुरू किया था और इसको आपने आगे बढ़ाया, यह बहुत अच्छी बात है। चाय पीने जाओ, तो स्वच्छता शुल्क लगता है।

(HMS/2J पर जारी)

RSS-HMS/2.35/2J/

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत) : समोसा खाने जाओ, तो स्वच्छता शुल्क लगता है। आज रेस्टॉरेंट में और हर जगह आप स्वच्छता शुल्क ले रहे हैं। सर, मेरे पास इस के आंकड़े हैं, जिनके अनुसार 9800 करोड़ रुपया इस में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन यह रुपया कहां जा रहा है? आप सिर्फ टॉयलेट्स बनाने की बात कह रहे हैं। महोदय, सब से बड़ी समस्या खुली नालियों की है। जब तक आप सीवेज सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक सिर्फ टॉयलेट्स बनाने से वह वेस्टेज या मल कहां जाएगा? वह तो नालियों में खुला घूमता

रहता है जिस कारण ज्यादा infection फैलता है और उससे ज्यादा बैक्टीरियाज़ जनरेट होते हैं। इसलिए आप साथ-साथ सीवेज सिस्टम बनाने की योजना शुरू करिए। आप इस पैसे से सरकार की तरफ से जगह-जगह डस्टबिन्स रखवाइए। आप ग्रीन ब्रिगेड बनाइए और इस तरह से गरीब युवकों को रोजगार दीजिए। ये ग्रीन ब्रिगेड के लोग कपड़े पहनकर जगह-जगह कूड़े की सफाई करें। आप डस्टबिन रखिए, सीवेज सिस्टम बनवाइए ताकि खुली नालियां खत्म हों। तब जाकर यह कार्यक्रम comprehensively चालू हो पाएगा। आप रेल लाइंस के किनारे-किनारे चले जाइए, आपको बहुत गंदगी देखने को मिलेगी और जब कोई विदेशी हमारी ट्रेन में बैठकर जाता है, तो वह देखकर अचम्भित हो जाता है कि क्या कोई देश ऐसा भी हो सकता है? स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आप इसे एक comprehensive plan के तौर पर चलाइए और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट की सारी व्यवस्था कीजिए। अगर आप इस तरह चलाएंगे तो यह भारत देश के लिए बड़ी अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन खाली इसके प्रचार और विज्ञापन से काम नहीं होगा।

दूसरी बात, आप हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, यह अच्छी बात है, चाहे वह आधार कार्ड की योजना हो। मैं जब योजना मंत्री था तो 167 करोड़ आधार कार्ड बन चुके थे। आपने इस योजना को आगे बढ़ाया, यह बहुत बढ़िया बात है। हमारे insurance reforms को आपने आगे बढ़ाया, अच्छी बात है। आपने banking reforms को बढ़ाया, अच्छी बात है। राजीव जी ने Digitisation और Computerisation शुरू किया था, उस समय उन की आलोचना हुई थी, आप इसे आगे ले जा रहे हैं, हम इस के लिए कोई

आलोचना नहीं करते बल्कि यह अच्छी बात है, लेकिन यह मत कहिए कि हमने यह सब शुरू किया है, इस के पहले कुछ था ही नहीं। यह श्रेय लेने की होड़ में कहीं ऐसा न हो कि आप पहले के लोगों के किए काम को भुला दें। महोदय, अटल जी के कामों का भी कोई जिक्र नहीं होता। अटल जी ने कभी श्रेय नहीं लिया कि यह मैंने किया। जो पिछले काम अच्छे थे, उन्होंने आगे बढ़ाया। आप भी वैसा कर रहे हैं, यह अच्छी चीज है।

मैं एक बात ज्यूडिशियरी के बारे कहना चाहूंगा। महोदय, करीब ढाई करोड़ केसेज कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, लेकिन विवाद चल रहा है और ज्यूडिशियरी से टकराव भी चल रहा है। इस बारे में कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए। आप National Judicial Appointments Commission का एक बिल यहां लाए थे, जोकि unanimously पास हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे टर्न डाउन किया और कहा कि इस में कुछ improvement होना चाहिए। आप उसे दोबारा से improve कर के या चेंजेज कर के ला सकते थे। अब न वह आ रहा है और न यह आ रहा है। इस वजह से ज्यूडिशियरी में किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भारत सरकार में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति महोदय, प्रधान मंत्री, मंत्री, एम0पी0 और एम0एल0ए0 तक की अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन एक जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में संसद को और सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर उनकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी हो। हर सेक्टर में रिफॉर्म्स हों - आसमान में रिफॉर्म हो, जमीन पर रिफॉर्म हो, सब का रिफॉर्म हो, लेकिन ज्यूडिशियरी में कोई रिफॉर्म न हो। यह कौनसा attitude है? वहां भी रिफॉर्म होना चाहिए। आज ज्यूडिशियरी की बहुत आलोचना हो रही है, बहुत बातें हो

रही हैं। आज जजेज़ भी कह रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि यह सिस्टम opaque है। यह कोलीजियम सिस्टम मनमाने ढंग से चलाया जाता है। सर, यह तो बहुत गंभीर बात है। अगर कोलीजियम का एक मेंबर कह रहा है, तो इस बात का नोटिस लेकर गवर्नमेंट को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। इस बारे में संसद आपके साथ है। इसलिए आपको इस बारे में कदम जरूर उठाना चाहिए। आप इसे बीच में छोड़कर भाग गए, यह बात ठीक नहीं है। ..(समय की घंटी)..

सर, आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिए हम अपनी पूरी बात नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखी हैं। आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए और जो डेढ़ साल आपका बचा है, उस डेढ़ साल में ये सारा काम कीजिए वरना बशीर बद्र साहब ने फरमाया है कि,

"शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है,
जिस साख पर बैठे हो, वह टूट भी सकती है।"

इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should translate it also. You should translate the couplet.

SHRI RAJEEV SHUKLA: The fame is a very temporary thing. Otherwise, we are sitting on a branch of a tree which can break also.

(Ends)

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, यह मेरी maiden speech है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Maiden speech means, you can take maximum 15 minutes.

श्री संजय सेठ : सर, हम दो लोगों को ही बोलना था, जितना समय बचा हो दे दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I said. Maiden speech के लिए maximum time 15 minutes.

(2 के/एएससी पर आगे)

ASC-KGG/2.40/2K

श्री संजय सेठ : सर, over and above....

श्री उपसभापति : बोलिए, बोलिए।

श्री संजय सेठ : सर, मैं सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि उनके उद्बोधन में बहुत ही नीतियां और योजनाएं गलत हैं। उसमें बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है, जैसे किसी फाइल की नोटिंग में होता है। जिसमें जमीन के धरातल पर क्या-क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है।

सर, इसमें सबसे पहले इन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास' के बारे में कहा है। मैं मानता हूं कि उसमें यह बिल्कुल गलत नारा है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि इस केन्द्र सरकार ने जहां-जहां बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें हैं, वहां उनको पूरे सहयोग और विकास में सहायता दी है, लेकिन जहां गैर बीजेपी शासित

प्रदेश हैं, वहां पर इन्होंने उनका कोई साथ नहीं दिया है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बहुत सारी केन्द्र से संबंधित योजनाएं हैं, जिनके लिए हम लोगों ने केन्द्र से पैसा मांगा था। हम लोगों ने पिछले सत्र में भी आपका ध्यान उनकी ओर दिलाया था, लेकिन आज तक इन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 'सबका साथ, सबका विकास' बिल्कुल नहीं हो रहा है। यह सिर्फ इनका अपना विकास हो रहा है।

सर, अभी तक केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही थीं, वे सबकी सब अब पीछे चली गई हैं, सिर्फ एक नोटबंदी की योजना ही दिख रही है। इस नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश की सरकार को हुआ है, क्योंकि आबादी के हिसाब से यह सबसे बड़ा प्रदेश है। सर, हमारे यहां किसानों की सारी फसलें, उपजें, खराब हो चुकी हैं। उनका सारा सामान नष्ट हो चुका है। किसानों को बीज नहीं मिला, fertilizer नहीं मिला, जिसके कारण उनका यह सारा सीज़न खराब हो गया। जब किसान का एक सीज़न खराब होता है, तो पूरे दो साल तक उसकी आर्थिक चीजें खत्म हो जाती हैं। किसानों के लिए जो कर्ज़ माफी थी, उसके लिए आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है।

सर, श्रमिकों का भी बहुत बुरा हाल है। सारे कंस्ट्रक्शन की लेबर वापस चली गई है। उनके पास पैसा नहीं है और सब अपने-अपने क्षेत्रों से वापस जाकर पलायन कर चुके हैं। सर, व्यापारियों का हाल तो सबसे बुरा है। आज उनके 40 से 50% बिजनेस खत्म हो चुके हैं। आज उनके पास पैसा न होने की वजह से उनको अपने बिजनेस से

कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है। सर, कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं, तो बेरोजगारी का लेवल अब एक बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस नोटबंदी में जो एक चीज देखने में आई, वह यह कि इस पीरियड में सैकड़ों सर्कुलर जारी हुए। कुछ ऐसे सर्कुलर भी जारी किए गए, जो मज़ाक का विषय बने। जैसे एक विषय बना कि आप केवल पांच हजार रुपए जमा कर सकते हैं। जब उसका मज़ाक बना, तो उसको 24 घंटों में ही वापस कर दिया गया। यह सब शो करता है कि किसी प्लानिंग के हिसाब से ये सारी चीजें नहीं हो रही थीं।

सर, इसके बाद इन्होंने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ सबका ध्यान खींचा। जिस देश के अंदर ग्रामीण अंचलों में आदमी सिग्नेचर नहीं कर पाता है, अंगूठा लगाता है

(उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) पीठासीन हुए)

और उसको स्मार्ट फोन से मोबाइल बैंकिंग के लिए कहा जाए, तो यह बड़ी हंसी की चीज नजर आती है। इन लोगों को सबसे पहले साक्षरता की तरफ देखना चाहिए था, इसके बाद ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था।

सर, ATMs की जो पोजिशन है, इसमें यहां पर एक लाख पर बीस ATMs हैं, जबकि पूरे विश्व में तकरीबन एक लाख की आबादी पर सौ ATMs होते हैं। अब मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि इसमें secrecy रखने की क्या जरूरत थी? पहले इसको कर लिया जाता, तब नोटबंदी और कैशलेस का काम किया जाता।

(2L/LP पर जारी)

LP-KLS/2.45/2L

श्री संजय सेठ (क्रमागत) : सर, इनकी एक "प्रधान मंत्री आवास योजना" है। यह एक अच्छी योजना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैंने भी एक वेबसाइट खोलकर देखी तो उसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि इसको कौन, कैसे और कहाँ से अवेल करेगा? इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जब आप सब चीज़ों के इतने विज्ञापन देते हैं, तब इसकी भी डिटेलिंग होनी चाहिए कि इसको कोई कैसे अवेल कर सकता है और कैसे उसके इंटरेस्ट की सब्सिडी उसको मिल सकती है?

सर, यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में हम लोगों की एक "समाजवादी आवास योजना" चल रही है। उस "समाजवादी आवास योजना" के अंदर हम लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सारे आवास उपलब्ध करवा रहे हैं। वहाँ पर यह योजना हाथों-हाथ चल रही है और करीबन लाखों मकान इस योजना के अंतर्गत बन रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से कहूंगा कि उस योजना को देखे और दूसरे स्टेट्स में भी उसको लागू करे।

सर, मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूंगा कि अगर केंद्र सरकार गरीबों को मकान देने के लिए बहुत जिम्मेदारी से कह रही है, तो उनको, किसी गरीब आदमी को दो कमरों का एक मकान इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में देना चाहिए। आज के दिन में, जिसकी 10-15 हज़ार रुपये की तनख्वाह है, वह इंटरेस्ट नहीं दे सकता है, चाहे उसको सब्सिडी भी मिल रही हो। दो कमरों का मकान प्रोवाइड कराने के लिए उस पर लोन का इंटरेस्ट नहीं पड़ना चाहिए।

सर, मैं यह मानता हूं कि "Right to Housing" एक Fundamental Right की तरह होना चाहिए और संसद में शीघ्र ही एक कम्पल्सरी हाउसिंग बिल भी लाना चाहिए।

सर, इसके बाद "स्वच्छ भारत मिशन" का जिक्र किया गया है। यह बहुत अच्छी योजना है। हमारे हिसाब से, पूरे भारतवर्ष को इसमें पूरा सहयोग देकर यह कार्य करना चाहिए, लेकिन आज के दिन में जो टॉयलेट्स बन रहे हैं, "स्वच्छ भारत अभियान" के अंदर जो सबसे मेजर चीज़ चल रही है, उसमें उसकी मेंटेनेन्स का कोई तरीका नहीं है। जितने भी टॉयलेट्स बने हैं, उनमें किसी का दरवाज़ा टूट गया है, किसी की सीट टूट गई है, किसी की छत टूट गई है। वह पैसा बरबाद हो रहा है। वह कैपिटल अमाउंट टोटली बरबाद हो रहा है। मेरा केंद्र सरकार को यह सजेशन होगा कि जैसे हमारे सुलभ शौचालय की एक मेंटेनेन्स एजेंसी है, वैसे ही, उस तरह की किसी एजेंसी को लगाना चाहिए, जो इसको मेंटेन कर सके।

सर, इस "स्वच्छ भारत अभियान" में जो बहुत बड़ी चीज़ है, वह यह है कि सारे शहरों के गंदे नाले और नालियाँ नदी में गिर रहे हैं। प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह एसटीपी लगाकर, उसका पानी साफ़ करके नदियों में गिराए। चूँकि हम लोग स्वच्छ भारत का सरचार्ज भी ले रहे हैं और इनके पास पैसा भी आ रहा है, इसलिए इन स्टेट्स को एसटीपी लगाने का पैसा मिलना चाहिए, जिससे हमारी नदियाँ साफ़ हों। यदि नदियाँ साफ़ होंगी, तो शहर और उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों को फायदा मिलेगा।

सर, मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं और कॉरपोरेट्स हैं, बैंकों के मुख्यालय हैं, वे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ़ नहीं हैं। चूँकि हमारी पॉप्युलेशन ज्यादा है, इसलिए उनको सबसे ज्यादा बिजनेस भी हम लोगों से ही मिलता है। उनकी सीएसआर के तरीके से केंद्र सरकार को ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि वह पैसा, जो बिजनेस कर रहा है, उसको अपनी एक सर्टेन परसेन्टेज सीएसआर के रूप में उस स्टेट में खर्च करनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर टॉयलेट का काम हो सके या और अन्य जो भी सीएसआर के रूप में काम हो सकते हैं, वे काम हो सकें।

सर, इस पूरे अभिभाषण में इनफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है। मेरा यह मानना है कि इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी भी योजनाएँ आपके यहाँ से चलाई जा रही हैं, वे ज़मीन पर नहीं दिख रही हैं। हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 23 महीनों में 302 किलोमीटर का लखनऊ-आगरा का एक एक्सप्रेस-वे, बनाकर तैयार कर दिया। सर, 23 महीनों में मकान नहीं बनता है, लेकिन हम लोगों ने 302 किलोमीटर की लैंड एक्विजिशन करके इसको पूरा तैयार कर दिया और आज वह चालू भी हो चुका है।

(klg/2m पर जारी)

KLG-SSS/2M/2.50

श्री संजय सेठ (क्रमागत): जिस वक्त आपकी सरकार बनी थी, वहां के सांसद ने यह कहा था कि लखनऊ के अंदर एक आउटर रिंग रोड बनेगी, लेकिन आज ढाई, पौने

तीन साल हो गए हैं और अभी तक उसकी शुरुआत कहीं नहीं हुई है। अगर आप इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तेजी से काम नहीं करेंगे, तो स्कीम्स फाइलों में पड़ी रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। ऐसा सिर्फ बातों से नहीं चलना चाहिए।

महोदय, विदेश-नीति के बारे में भी इसमें कहा गया है। हम लोगों के अमरीका के साथ बहुत अच्छे संबंध बताए जा रहे थे, लेकिन जब से नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, वे H-1B वीज़ा को कम कर रोजगार हटाने की बात करने लगे हैं। इस पर हमारी सरकार को उनसे जाकर बात करनी चाहिए कि हमारे इतने नौजवान वहां काम कर रहे हैं, वे नौकरी से न हटें। अगर कुछ होता है, तो हमें अपने देश के अंदर उनको रोजगार देने के लिए कुछ इकाइयां, कुछ नौकरियां ऐसी तैयार करनी चाहिए, जिससे वे यहां पर आएं तो उनको नौकरी मिले, वे बेरोजगारी न रहें। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी आज इतनी बेरोजगारी होती जा रही है कि 2016 के आखिरी क्वार्टर में 23 हजार आदमी काम से निकाले गए हैं। सब तरफ आज एक ऐसा माहौल बन रहा है, जिसे देखकर लगता है कि सब तरफ लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। इसको आपको देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी कुछ ऐसी इकाइयां लाने का आपका विचार होना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के नौजवान कहीं और न जाएं, उसी प्रदेश मे काम करें, चाहे वे सरकारी इकाइयां हों या अर्ध-सरकारी इकाइयां हों, उनको उनमें नौकरियां मिलें।

महोदय, स्वास्थ्य के बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। हम लोगों की उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक समाजवादी स्वास्थ्य सेवा करके 108 नंबर की एम्बुलेन्स सेवा

शुरू की है और वह इतनी सक्सेसफुल हो रही है कि जिसको एम्बुलेन्स सेवा की जरूरत होती है, दस मिनट में उसके पास पहुंचती है। हम लोग अपने संसाधनों से तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से हमें ऐसी कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिससे हम उसको और आगे बढ़ा सकें। हम चाहेंगे कि उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार को मदद मिले। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एनवार्यनमेंट का भी इसके अंदर कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। इस प्रदूषण से निपटने के लिए क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में एक दिन में पांच करोड़ पेड़ लगाकर गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड ...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): एक मिनट बचा है।

श्री संजय सेठ: सर, बस एक मिनट। हम लोगों ने पांच करोड़ पेड़ लगाए। आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कई सम्मानित व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिनकी शताब्दी, जन्म शताब्दी आदि मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई स्वतंत्रता सेनानियों और उपन्यासकारों के पैतृक स्थान हैं, जैसे चन्द्रशेखर आज़ाद जी, मुंशी प्रेमचन्द जी, आज उनके पैतृक स्थानों की हालत बहुत ही खराब है, उनके मकान वगैरह गिर चुके हैं। हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार वहां पर भी उनके ऐसे स्मारक बनाए या ऐसे रिस्टोर करे, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी उनको पूरी तरह से देख सके। इसी क्रम में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने डा. मुरली मनोहर जोशी जी और शरद पवार जी को "पद्म विभूषण" से सम्मानित किया है। हमारे देश में एक गरीब किसान के घर में जन्म लेकर, लोहिया जी

के सिद्धांतों पर चलकर पिछले पचास वर्षों से किसानों, गरीबों के मसीहा धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। इन्होंने देश के सभी वर्गों, धर्मों और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है, तीन बार आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और एक बार देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इनको भी सरकार "पद्म विभूषण" से सम्मानित करे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

(2एन/एकेजी-एनबीआर पर आगे)

AKG-NBR/2N/2.55

श्री शरद यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का जो उद्बोधन है, उस पर काफी लोगों ने बहुत विस्तार से कहा है। मैं राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर धन्यवाद के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दौर का एक बड़ा फैसला नोटबंदी का हुआ है। इस सदन में एक-दो पार्टियों को छोड़ कर इस कदम का, चूँकि सरकार इसे काले धन के खिलाफ लाई थी, लोगों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसमें उसका ज़िक्र तो है, लेकिन इसके नतीजे क्या हुए, कितना काला धन आया, यह सरकार को बताना चाहिए। कितने नकली या फर्जी नोट मिले और बैंक में कितना पैसा जमा हो गया, सरकार को यह भी बताना चाहिए। अभी राजीव शुक्ल जी ने काफी विस्तार से बताया कि किस-किस चीज में किस-किस तरह से नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुए हैं, मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं

इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस सारी नोटबंदी के मामले से एक बड़ी आबादी बहुत तकलीफ में आई है। सब्जी उगाने वाले जो किसान हैं, वे हिन्दुस्तान में बहुत small farmers हैं या फिर वे किसी से खरीद कर सब्जी लेते हैं। मैंने उनकी पहचान की है, लोगों से पता लगाया है, वे साढ़े तीन करोड़ लोग हैं। इस नोटबंदी के मामले में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत, किल्लत और तबाही किसी की हुई है, तो ये जो साढ़े तीन करोड़ लोग हैं, जो सब्जी-भाजी जैसे perishable items उगाते हैं, उनकी हुई है। यहाँ किसानों की चर्चा होती है, लेकिन ये किसान बड़ी तादाद में हैं। इसके उत्पादन में बहुत पैसा लगता है। ये items इस बार खेत में ही सड़ गए। अगर वे उनको बाजार में लाए भी हैं, तो वे उनका किराया तक नहीं चुका पाए। उनकी ऐसी हालत हुई है। बाकी और रोजगार कितने गए हैं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो भारतीय मजदूर संघ है, उसने कहा है कि करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया है। उसके बाबत इस अभिभाषण में कोई ज़िक्र नहीं है।

सर, कश्मीर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में कभी हालत इतनी नहीं बिगड़ी, जितनी आज है। अभी ऐसा मौसम है, जिसकी वजह से वहाँ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस मौसम के खत्म होने के बाद जैसे ही बर्फ पिघलेगी, बर्फबारी जाएगी, यह सीज़न जाएगा, उसके बाद कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अभी मौका है, आप इस सवाल को हाथ में लीजिए। आपने जो agenda for alliance रखा है, उसमें आपने सब तरह के लोगों से बात करने

की बात कही थी। वहाँ 70 लोगों की जानें पैलेट गन और गोलियों से चली गईं। हमारे सिक्योरिटी फोर्स के लोगों की जानें चली गईं। वहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण हैं।

(2ओ/एससीएच पर जारी)